(ख) यदि हां, तो ऐसे पलायन को रोकने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार गांवों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कोई राष्ट्रव्यापी योजना शुरू करने जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागोड़ा पाटील): (क) से (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध न होने के कारण शहरी क्षेत्रों में प्रवास बढ़ने का एक कारण है। ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:- जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, दस लख कुंओं की योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, और ट्राइसेम।

गांवों में पेयजल हेतु निधियों का दुरुपयोग

1677. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 1985 से अब तक 15,229 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की गई है लेकिन बासठ हजार गांवों में आज भी पर्याप्त मात्रा में पेयजल की व्यवस्था का अभाव है;

(ख) क्या यह भी सच है कि 3.78 लाख गांवों में भी यह व्यवस्था आंशिक रूप से की गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस संबंध में निधियों का बहुत भारी मात्रा में दुर्विनियोजन किया है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागोड़ा पाटील): (क) से (ग) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है। राज्य सरकारें राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम का कार्यान्वयन करती रही हैं। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग देती है। राज्य सरकारों द्वारा दिसम्बर, 1998 तक दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 1985 से त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत 8390.48 करोड़ रुपये और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत 11395.81 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। 1.1.1999 की स्थिति के अनुसार कुल 1430663 ग्रामीण बसावटों में से 1126258 ग्रामीण बसावटों को पूर्णत: और 260071 ग्रामीण बसावटों को आंशिक रूप से स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। शेष 44334 ग्रामीण बसावटें न कि गांवों को अभी स्वच्छ पेयजल मुहैया कराया जाना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार कार्य योजना के अनुसार पश्चिमी राजस्थान की कुछ बसावटों को छोड़कर शेष सभी बसावटों को नौवीं योजना के अन्त तक कवर कर लिया जाएगा बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों। बसावटों को कवर न कर पाने का कारण निधियों की कमी, मौके पर पर्याप्त स्रोतों की कमी और प्रशासनिक अड़चनें थीं।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए ऋणों पर निगरानी

1678. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई॰आर॰डी॰पी॰) के अंतर्गत दिए गए ऋणों और अनुदानों से कितने लोगों को लाभ पहुंचा है;

(ख) क्या इन ऋणों और अनुदानों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार के पास कोई स्थायी निगरानी नेटवर्क है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त शीर्ष के अंतर्गत राजस्थान को कितनी निधियां उपलब्ध करायी गयी है और इससे कितने लोगों को लाभ पहुंचा है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागोड़ा पाटील): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित व्यक्तियों की कुल संख्या 57.20 लाख है।

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की निगरानी मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक आधार पर की जाती है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में सहायता के समुचित और पूर्ण उपयोग के लिए निधियों के उपयोग के त्रैमासिक लक्ष्य रखे गए हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की विभिन्न स्तरों पर नियमित निगरानी की जा रही है। राज्य स्तर पर एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति कार्यक्रम की निगरानी करती है। केन्द्र स्तर पर इस मंत्रालय ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम सहित विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की क्षेत्र अधिकारी योजना के जरिए निगरानी को मजबूत बनाने का प्रयास किया है जिसमें मंत्रालय के अधिकारी कार्यक्रम के क्षेत्र के दौरे करते हैं और कार्यक्रम के कार्यान्वयन की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के निर्धारित

दिशा-निर्देशों के अनुसार निधियों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य, जिला और खण्ड स्तरों पर सतर्कता और निगरानी समितियां गठित करने के लिए भी मंत्रालय ने अनुदेश जारी किए हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में लगभग 2.24 लाख व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 10689.13 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में और 35826.83 लाख रुपये की राशि ऋण के रूप में प्रदान की गई है।

Shortage of cold storage facilities

1679. SHRI C.O. POULOSE: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the names of the States where there are acute shortage of cold storage facilities; and

(b) the steps Government have taken to improve the situation so far?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) Bihar, Orissa, Uttar Pradesh and West Bengal are the main States where there is shortage of cold storage facilities.

(b) A High Level Expert Committee had been set up in the Ministry of Agriculture to suggest and recommend steps to be taken to augment the cold storage capacity. The Committee has submitted its report in February, 1999. The Committee has recommended to increase the cold storage capacity to 123 lakh tons from the existing 103 lakh tons. The Committee has also recommended that Government of India may assist creation of storage facilities for stocking potato, onion and other commodities. For this, incentives like interest subsidy and capital investment subsidy are to be provided. It has been decided to provide such incentives through the National Co-operative Development Corporation (NCDC), the National Horticulture Board (NHB), the National Bank of Agriculture and Rural Development (NABARD), Banks and financial Institutions.

Construction of houses under IAY in Gujarat

1680. SHRI BRAHMA KUMAR BHATT: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state the details of places in Gujarat, particularly in the backward areas district-wise and region-wise where free of cost residential houses have been constructed for the poorest people under Indira Awas Yojana during the last two years?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): According to information received from Government of Gujarat Indira Awaas Yojana (IAY) is being implemented in all the 19 districts of Gujarat including 8 backward districts/areas namely Dangs, Panchamahals, Banaskantha, Bharuch, Vadodara, Valsad, Sabarkantha and Surat. The district-wise and region wise number of houses constructed including backward districts under IAY in Gujarat during last two years is given in the enclosed statements below.

Statement

Free of cost Houses constructed under IAY

Sl. No.	Name of District	During 1996-97	During 1997-98
1.	Ahmedabad	682	407
2.	Amreli	574	444
3.	Banaskantha	1544	954
4.	Bharuch	3914	2629
5.	Bhavnagar	668	347
6.	Dangs	400	423
7.	Gandhinagar	65	40
8.	Jamnagar	350	216
9.	Junagarh	731	702
10.	Kheda	504	510
11.	Kutch	852	487
12.	Mehsana	677	567
13.	Panchmahal	6546	4065
14.	Rajkot	486	322
15.	Sabarkantha	1249	1327
16.	Surat	3523	4358
17.	Surendranagar	467	528
18.	Vadodara	2322	3064
19.	Valsad	4927	3049
	TOTAL	30481	24439